



## प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ

### प्रलिस के लयः

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, सहकार से समृद्धि, सहकारी, [उरवरक](#), आत्मनरिभर भारत

### मेन्स के लयः

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ

## चरचा में क्योँ?

प्रधानमंत्री के "सहकार से समृद्धि" के वज़िन को साकार करने की दशिया में सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (Primary Agricultural Credit Societies- PACS) की आय में वृद्धि करने के साथ-साथ ग्रामीण कृषेत्तरोँ में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लयि पाँच नरिणय लयि हैं।

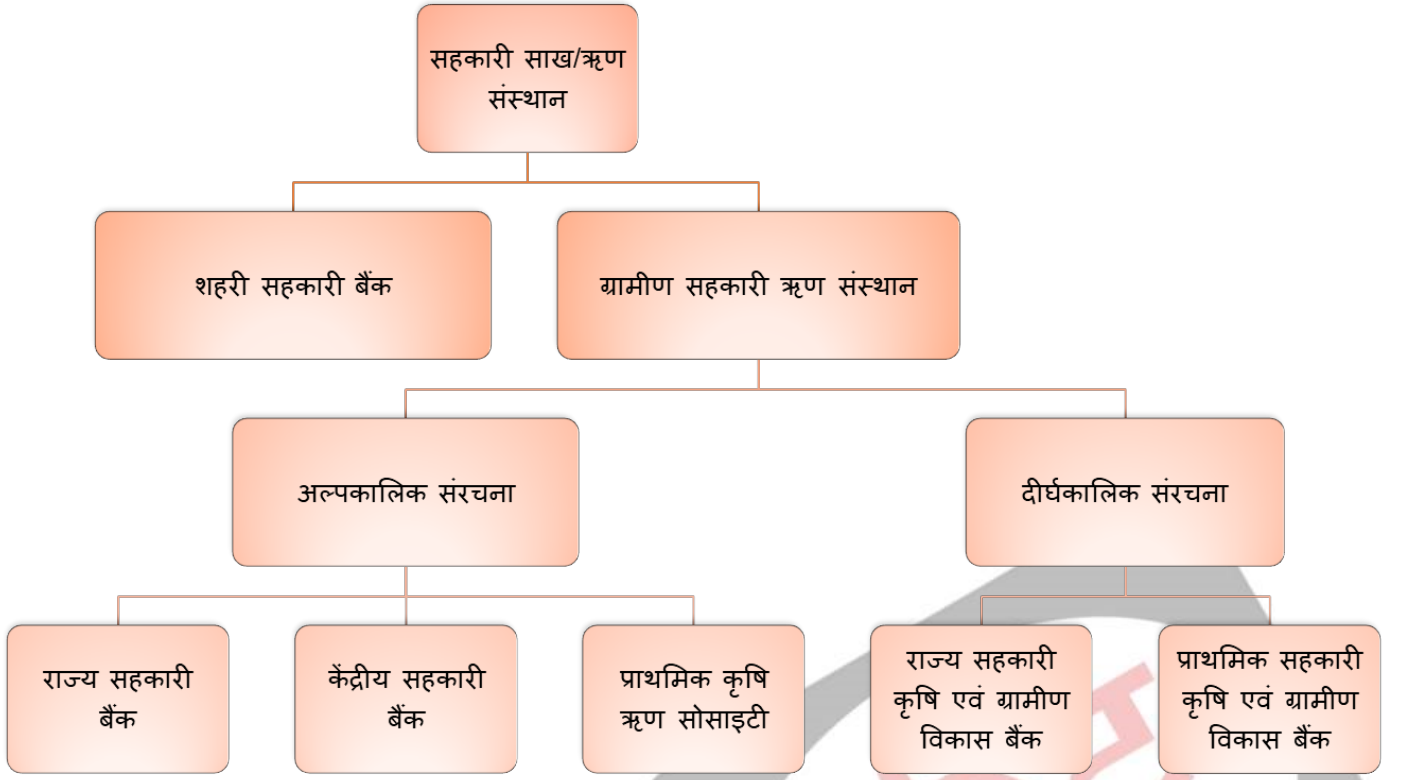
- सरकार का लक्षय "सहकार से समृद्धि" के माध्यम से देश में समगर समृद्धि का उद्देश्य प्राप्त करना है। इसे पारदर्शति, आधुनिकीकरण और प्रतसिप्रद्धात्मकता द्वारा सहकारी समितियाँ को सुदृढ़ बनाने के लयि प्रस्तावति कयि गया था।

## पाँच महत्त्वपूर्ण नरिणयः

- उरवरक खुदरा वकिरेताओँ के रूप में कार्य नहीं कर रहे PACS की पहचान की जाएगी और उनहें चरणबद्ध तरीके से व्यवहार्यता के आधार पर खुदरा वकिरेताओँ के रूप में कार्य करने के लयि प्रोत्साहति कयि जाएगा।
- वर्तमान में प्रधानमंत्री कसिन समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में काम नहीं कर रहे PACS को PMKSK के दायरे में लाया जाएगा।
  - प्रधानमंत्री ने रसायन और उरवरक मंत्रालय के तहत वर्ष 2022 में 600 PMKSK का उद्घाटन कयि।
  - ये केंद्र कसिनोँ की वभिनिन प्रकार की जरूरतोँ को पूरा करेगे और कृषि-इनपुट, मृदा, बीज तथा उरवरक के लयि परीक्षण सुवधिएँ भी प्रदान करेगे।
- जैवकि उरवरकोँ, वशिष रूप से फरमेंटेड जैवकि खाद (FoM)/ तरल फरमेंटेड जैवकि खाद (LFOM) / फॉस्फेट समृद्ध जैवकि खाद (PROM) के वपिणन में PACS को जोड़ा जाएगा।
- उरवरक वभिणन की मार्केट डेवलपमेंट अससिटेस (MDA) योजना के तहत उरवरक कंपनयिओँ छोटे बायो-ऑर्गेनिक उत्पादकोँ के लयि एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य कर अंतमि उत्पाद का वपिणन करेगी, इस आपूर्ति और वपिणन श्रृंखला में थोक/ खुदरा वकिरेताओँ के रूप में PACS को भी शामिल कयि जाएगा।
- उरवरक और कीटनाशकोँ के छड़िकाव के लयि PACS को ड्रोन उद्यमयिओँ के रूप में भी इस्तेमाल कयि जा सकेगा, साथ ही, ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लयि भी कयि जा सकता है।

## प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ:

- परचियः
  - PACS ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियाँ हैं जो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकोँ (State Cooperative Banks- SCB) की अध्यक्षता वाली त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतमि कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।
    - SCB से क्रेडिट का हस्तांतरण ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकोँ (District Central Cooperative Banks- DCCB) को कयि जाता है, जो ज़िला स्तर पर काम करते हैं। ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक PACS के साथ काम करते हैं, साथ ही ये सीधे कसिनोँ से जुड़े हैं।
  - PACS वभिनिन कृषि और कृषिगतविधियिओँ हेतु कसिनोँ को अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करते हैं।
  - पहला PACS वर्ष 1904 में बनाया गया था।



//

#### ■ स्थिति:

- भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा 27 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में PACS की संख्या 1.02 लाख बताई गई है। मार्च 2021 के अंत में इनमें से केवल 47,297 लाभ की स्थिति में थे।

#### ■ महत्त्व:

##### ○ क्रेडिट तक पहुँच:

- वे छोटे किसानों को ऋण तक पहुँच प्रदान करते हैं जिसका उपयोग वे अपने खेतों के लिये बीज, उर्वरक और अन्य सामग्री खरीदने के लिये कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने उत्पादन में सुधार करने तथा आय बढ़ाने में मदद मिलती है।

##### ○ वित्तीय समावेशन:

- PACS ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं जहाँ औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सीमित है। वे उन किसानों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं जैसे- बचत और ऋण खाते जिनकी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं हो सकती है।

##### ○ सुवधाजनक सेवाएँ:

- PACS प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति होते हैं जो किसानों के लिये उनकी सेवाओं तक पहुँच को सुवधाजनक बनाता है। PACS में कम समय में न्यूनतम कागज़ी कार्रवाई के साथ ऋण देने की क्षमता है।

##### ○ बचत संस्कृतिको बढ़ावा देना:

- PACS किसानों को पैसे बचाने के लिये प्रोत्साहित करती है जिसका उपयोग उनकी आजीविका में सुधार करने और उनके खेतों में

नविश करने के लिये किया जा सकता है।

• **क्रेडिट अनुशासन को बढ़ाना:**

- PACS समय पर अपने ऋण चुकाने के लिये कसिनो के बीच ऋण अनुशासन को बढ़ावा देती हैं। ये डिफॉल्ट के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं जो ग्रामीण वित्तीय क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

## PACS संबंधी मुद्दे:

■ **अपर्याप्त कवरेज:**

- हालाँकि भौगोलिक रूप से सक्रिय PACS 5.8 गाँवों में से लगभग 90% को कवर करते हैं लेकिन देश के कुछ हिस्से (वशिष्टतः उत्तर-पूर्व में) ऐसे हैं जहाँ यह कवरेज बहुत कम है।
- इसके अलावा सदस्यों के रूप में शामिल की गई ग्रामीण आबादी सभी ग्रामीण परिवारों का केवल 50% है।

■ **अपर्याप्त संसाधन:**

- PACS के संसाधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लघु और मध्यम अवधि की ऋण आवश्यकताओं के संबंध में अपर्याप्त हैं।
- यहाँ तक कि इन अपर्याप्त नधियों का बड़ा हिस्सा उच्च वित्तपोषण एजेंसियों से आता है, न कि समितियों के स्वामित्व वाले वित्तपोषण या उनके द्वारा जमा संग्रहण के माध्यम से।

■ **अतद्विध और NPA:**

- PACS हेतु बड़ी बकाया राशिएक बड़ी समस्या बन गई है।
  - वर्ष 2022 में RBI की रिपोर्ट के अनुसार, PACS ने 1,43,044 करोड़ रुपए के ऋण और 72,550 करोड़ रुपए के NPA की सूचना दी थी। महाराष्ट्र में 20,897 PACS हैं जिनमें से 11,326 घाटे में हैं।
- वे ऋण योग्य धन के प्रवाह को सीमित करते हैं, उधार लेने और उधार देने हेतु समाज की क्षमता को कमजोर करते हैं और उन्हें यह आभास कराते हैं कि डिफॉल्ट देनदारों को लेकर समाज दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं।

## आगे की राह

- PACS भारत के ग्रामीण वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्थान हैं और [आत्मनिर्भर भारत](#) एवं [वोकल फॉर लोकल अभियान](#) के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ये सदस्यों पुराने संस्थान आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव के रूप में काम कर सकते हैं।
- अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिये PACS को अधिक कुशल, वित्तीय रूप से टिकाऊ और कसिनो के लिये सुलभ बनाने की आवश्यकता है। इसके लिये उनके संचालन एवं प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त प्रभावी प्रशासन और कसिनो की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिये PACS को नयित्त्रति करने वाले नयामक ढाँचे को मज़बूत किया जाना चाहिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

### प्रलिसः

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि ? (2020)

1. कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक ऋण वतिरण के संदर्भ में ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) अनुसूचिति वाणजियिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान करते हैं।
2. ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक प्राथमिक कृषि साख समितियों को धन उपलब्ध कराना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (B)

प्रश्न. भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

1. राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं वनियमन किया जाता है।
2. वे इक्वटी शेयर और अधिमिन शेयर जारी कर सकते हैं।
3. उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी वनियमन अधिनियम, 1949 के कार्य-क्षेत्र में लाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

**??????:**

प्रश्न. "गाँवों में सहकारी समितियों को छोड़कर ऋण संगठन का अन्य ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन की वविचना कीजिये। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को कनि बाधयताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और उनकी सेवा करने के लिये प्रौद्योगिकी का कसि प्रकार उपयोग किया जा सकता है? (2014)

**स्रोत: पी.आई.बी.**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/primary-agricultural-credit-societies-1>

